

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3730

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

हरियाणा में उच्च शिक्षा में सुधार

†3730. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा राज्य सरकार एक दशक से भी अधिक समय तक सत्तारूढ़ रहने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है, जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हरियाणा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वस्तुतः राज्य के शिक्षा बजट का कितना हिस्सा हरियाणा में उच्च शिक्षा सुधार पर व्यय किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा एक ऐसा विषय है जो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आता है, जहाँ केंद्र तथा राज्य-दोनों के पास कानून बनाने की विधायी शक्ति है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधान के अधिनियम द्वारा की जाती है, वे संबंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन में कार्य करते हैं तथा मौजूदा राज्य उच्च शिक्षण संस्थान की समग्र गुणवत्ता में सुधार हेतु विकास निधि मुख्य रूप से उस राज्य सरकार का मुद्दा है।

इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा फरवरी 2025 में प्रकाशित 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' पर रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके सभी राज्यों में उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अस्थायी विश्लेषण प्रदान करती है। उक्त रिपोर्ट में हरियाणा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता का कोई विशेष संदर्भ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य सरकार का व्यय प्रबंधन और निगरानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
